>

Title: Need to revise the income limit criteria for BPL families to cover maximum number of people so as to entitle them to food grains at subsidized rates, especially in Uttarkhand.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सदन के माध्यम से मुझे अवगत कराना है कि उत्तराखंड में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे एपीएल परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बीपीएल परिवारों को नियमित रूप से नियंत्रित खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसके कारण जन-आक्रोश बढ़ रहा है। यही नहीं, बल्कि बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय की सीमा मात्र दस हजार रुपये निर्धारित है, जबकि न्यूनतम मजदूरी सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बीपीएल परिवार की वार्षिक आय कम से कम 36 हजार रुपये निर्धारित की जानी चाहिए।

उत्तराखंड प्रदेश चीन और नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए सीमान्त राज्य होने के कारण भी एपीएल तथा बीपीएल परिवारों को नियमित रूप से नियंत्रित खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

MADAM SPEAKER : The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m.

13.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.